साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 78 | जौनपुर, शुक्रवार, 08 नवम्बर 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा

जम्मू कश्मीर, एजेसी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सात नवंबर को बड़ा हंगामा हुआ है। विधानसभा में लगातार ये हंगामा जारी है। विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हुई है। कहा जा रहा है कि ये हंगामा आर्टिकल 370 की वापसी के प्रस्ताव से संबंधित है। बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन की कार्यवाही के दौरान अनुच्छेद 370 से संबंधित बैनर दिखाया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त हंगामा हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई हुई है। इस तरह का बैनर दिखाए जाने के बाद बीजेपी नेता और विधायकों ने इसका विरोध किया। विधानसभा ने नेता विपक्ष और भाजपा नेता सुनील वर्मा ने बैनर दिखाए जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर मुद्दा इतना अधिक बढ़ा कि मार्शल को भी बीच बचाव करने के लिए बीच में आना पड़ा था। सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था।

राहुल गांधी नहीं करते संविधान का सम्मान – रिजिजू

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राहुल गांधी द्वारा नागपुर में संविधान सम्मेलन आयोजित करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी द्वारा नागपुर में संविधान सम्मेलन आयोजित करने पर आपत्ति है, जबकि वह संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान करने के बाद कांग्रेस को उनके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के जनक के रूप में जाने जाने वाले डॉ. अंबेडकर ने संविधान बनाने वाली मसौदा समिति का नेतृत्व किया। इससे पहले, बुधवार को, गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में चुनावी सभा में लाल कवर के साथ संविधान की एक पतली प्रति ली थी। गांधी की आलोचना करते हुए भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा, गांधी एक हाथ में संविधान रखते हैं और दूसरे हाथ से अराजकता को बढ़ावा देते हैं।

वह शहरी नक्सलियों और अराजकतावादियों से प्रभावित हैं जो कांग्रेस को कट्टरपंथी एजेंडे की ओर धकेल रहे हैं। राजनीति में लाल रंग को अक्सर मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़ा जाता है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवा पार्टी परेशान थी गांधी ने अपना कार्यक्रम नागपुर में भाजपा के गढ़ के पास आयोजित किया था।

दिग्गजों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने भारत के सशस्त्र बलों के दिग्गजों को याद करते हुए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के कार्यान्वयन को याद किया। ओआरओपी योजना के तहत सशस्त्र बलों के कार्मिकों को समान पद और सेवा अवधि के लिए समान पेंशन का भुगतान किया जाता है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में दिग्गजों को याद किया और कहा कि ओआरओपी उनके बलिदान और साहस को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। पोस्ट में लिखा गया है, इस दिन, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू किया गया था। यह हमारे दिग्गजों और पूर्व सैन्यकर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पोस्ट में आगे कहा गया, ओआरओपी लागू करने का निर्णय इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने तथा हमारे नायकों के प्रति हमारे राष्ट्र की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओआरओपी को लागू करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 7 नवम्बर, 2015 को लिया गया था, जिसके लाभ 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी होंगे। ओआरओपी सशस्त्र बलों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसका तात्पर्य यह है कि समान रैंक के सेवानिवृत्त सैनिक, जो समान सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

भोजपुरी समाज संपूर्ण विश्व में एक भारत-श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा

लखनऊ, संवाददाता। छठ महापर्व के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती घाट पर लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचे और छठ पर्व में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने वहां छठ पूजा किया और इसके बाद मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज छठ मां पर न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का उत्सव बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि भोजपुरी समाज आज संपूर्ण विश्व में छठ की सुगंध को अपने साथ ले जाकर एक भारत–श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। छठ महापर्व की हृदय से बधाई एवं इस आयोजन हेतु अखिल भारतीय भोजपुरी समाज को ढेरों शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारे पर्व और त्योहार तभी तक जीवित है, जब तक हमारा राष्ट्रीय धर्म जीवित है। पर्व–त्योहार हमें जोड़ते हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रीय धर्म भी होना चाहिए। राष्ट्रीय धर्म में हर काम देश के नाम होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं और उनका संकल्प भी यही है।

उन्होंने साफ तौर कहा कि हम जहां पर्व–त्यौहार के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रहकर भारत की संस्कृति, भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य जो लोग भी कर रहे हैं, किसी भी भारतवासी को यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब 140 करोड़ भारतवासी एकजुट होकर एक साथ बोलते हैं तो पूरी दुनिया हमारी बात सुनती है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में हटाए। उन्होंने कहा कि 370 समाप्त कर मोदी सरकार ने आतंकवाद पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को लगा कि यह नया भारत है। यह नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर कोई इस भारत को छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। यह भारत ना झुकेगा, ना डिगेगा। हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपनी एकता और अखंडता को मजबूत रखेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कांग्रेस के समय में उसे आतंकवाद का घर बनाने की कोशिश की गई थी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो कुछ लिखा गया था उसे अलग किया गया। किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई।

मोदी सरकार ने पेंशन विभाग को दिया नया स्वरूप - जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, एजेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन विभाग को एक नया स्वरूप दिया। इसे अब केवल पेंशन वितरित करने तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि बहुत से मानवीय सुधार भी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया है, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से पेंशन विभाग में कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य पेंशन वितरण को सरल और सुलभ बनाना था, ताकि पेंशनर्स को समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन मिल सके। उन्होंने आगे कहा, "पहला बड़ा सुधार यह था कि पेंशनरों

को जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए हर साल बैंक में (प्रमाणपत्र) जमा करना पड़ता था। यह प्रावधान विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए कठिनाई उत्पन्न करता था, जो वृद्धावस्था में होने के कारण स्वयं जाकर यह प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सकते थे। कुछ पेंशनर्स तो ऐसे थे जो 90 वर्ष या उससे ऊपर के थे, और उनके लिए यह प्रक्रिया बहुत कठिन और परेशानी भरी थी। उन्होंने आगे कहा, "इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मोदी सरकार ने तकनीकी सुधारों के माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की शुरुआत की। साल 2014–15 में इसकी शुरुआत हुई और यह योजना सफल रही। इसके बाद एक और बड़ा कदम उठाया गया। कई पेंशनर्स की उम्र बहुत बढ़ चुकी थी और उनकी उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) भी सही से नहीं आ पाते थे, जिससे बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या आती थी। इस समस्या का समाधान आधुनिक फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से किया गया। उन्होंने कहा, "यह पहली बार था जब भारत सरकार के किसी विभाग ने फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया और इसे पेंशन वितरण प्रक्रिया में शामिल किया। इसके तहत, पेंशनर्स को अपने मोबाइल फोन में कैमरे से खुद की तस्वीर खींचनी होती थी, और कुछ ही सेकंडों में आधार के माध्यम से उनका जीवन प्रमाणपत्र बैंक में उपलब्ध हो जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में पेंशनर्स को सिर्फ 30–40 सेकंड का समय लगता था, और जीवन प्रमाणपत्र तुरंत बैंक तक पहुंच जाता था। उन्होंने आगे कहा, "इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने सहयोग किया और पेंशनर्स को तकनीकी उपायों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

एनईपी के क्रियान्वयन में पीएम विद्यालक्ष्मी एक ठोस कदम – धर्मेंद्र

नई दिल्ली, एजेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि यह योजना मेधावी छात्रों की वित्तीय सहायता करेगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की प्रमुख सिफारिशों में से एक है। पीएम विद्यालक्ष्मी एनईपी के कार्यान्वयन की दिशा में एक और ठोस कदम है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों छात्रों को सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय क्षेत्र के तहत एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा तक पहुंच में बाधा न बनें। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में उल्लिखित विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) दोनों में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा श्पीएम विद्यालक्ष्मी योजनाश को मंजूरी दिए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रधान ने कहा कि यह योजना भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 21वीं सदी की उच्च शिक्षा तक एक समान पहुंच संभव बनाने में मदद करेगी। 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह योजना उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी। देश की युवा शक्ति को अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत जमानत–मुक्त और गारंटर–मुक्त शिक्षा ऋण से मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि वित्तीय बाधाओं के चलते छात्र शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें। 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट पाने के पात्र होंगे और 7.5 लाख रुपये तक के ऋण पर 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी मिलेगी।

आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी सरकार की जीरो टालरेंस की नीति – अमित शाह

नई दिल्ली, एजेसी। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन– 2024 के उद्घाटन सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने

संबोधित किया। शाह ने साफ तौर पर कहा कि हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिसकर्मी अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। मैं आज उन सभी को सर्वोच्च बलिदान देने की उनकी भावना के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और देश की ओर से उनके परिवारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के अंदर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आह्वान की दुनिया ने सराहना की है। वार्षिक सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाले खतरों पर विचार–विमर्श के लिए परिचालन बलों, तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों और आतंकवाद –रोधी एजेंसियों के लिए एक बैठक बिंदु के रूप में उभरा है।

पेपर लीक मामले पर घिरी हेमंत सोरेन सरकार

झारखंड, एजेंसी। झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जेएमएम गठबंधन सरकार के लिए विधानसभा चुनाव जीतने की राह मुश्किल होती जा रही है। दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी गड़बड़ियों के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। इन मुद्दों पर सरकार जनता को जवाब नहीं दे पा रही है। हाल ही में, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आये थे। इस दौरान उन्होंने परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा उठाकर सत्ताधारी जेएमएम पर निशाना साधा। इसी के साथ शाह ने जनता से वादा किया कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो एसआईटी द्वारा इन मामलों की जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, श्परीक्षा के 11 से ज्यादा पेपर लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश हैं क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे–बट्टे हैं। आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं, हम एसआईटी बनाकर पेपर लीक करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे बांधने का काम करेंगे।

हेमंत सरकार द्वारा हाल ही में पेपर लीक मामले से निपटने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। यह झारखंड के लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की गई है। कई लोगों का तर्क है कि अगर जेएमएम सरकार ने परीक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता दी होती, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता था। यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में संदिग्ध अनियमितताओं को नजरअंदाज किया और उचित कार्रवाई करने में विफल रही। इससे स्वाभाविक सवाल उठता है पेपर लीक क्यों हुआ? क्या सरकार में इसे रोकने की क्षमता की कमी थी या फिर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता में कमी थी? उल्लेखनीय रूप से, अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सरकार की ढीली प्रतिक्रिया के कारण संदेह पैदा हुआ। हेमंत सरकार को पेपर लीक रोकने के मामले में अपने कमजोर रुख के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस राज्य में शांति–व्यवस्था भंग करना चाहती है – अरूण साव

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के उप–मुख्यमंत्री अरूण साव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस बीच , उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह पार्टी नहीं चाहती है कि राज्य में शांति–व्यवस्था स्थापित हो। इसके लिए यह लोग राज्य में लगातार शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार अपराधियों को लेकर सख्त है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि कानून व्यवस्था के मामले में वह बहुत गंभीर हैं और इस पर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच हाथियों के विचरण की समस्या को दोनों राज्य मिलकर सुलझा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच इस तरह के कई अन्य मुद्दे हैं जिन्हें मिलकर हल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के स्तर पर दोनों राज्यों के बीच बातचीत चल रही है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर सकारात्मक हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा की शिकार हो चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि रायपुर दक्षिण का चुनाव वह हारने वाली है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का समर्थन मजबूत है। रायपुर दक्षिण की जनता जानती

सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। दरअसल, शीर्ष न्यायालय इस संबंध में सुनवाई कर रही थी कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी नियम में बदलाव किया जा सकता है या नहीं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। पीठ में न्यायमूर्ति ह्रषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया अनुच्छेद 14 के अनरूप होने चाहिए। पहले से जो नियम निर्धारित हैं, उसी के अनरूप पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव किए जाने से उम्मीदवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को देखते हुए शीर्ष न्यायालय का यह फैसला अहम हो जाता है। दरअसल, 2013 में राजस्थान सरकार ने अनुवादकों की भर्ती के दौरान नियमों में कुछ बदलाव किया था। इसमें कहा गया था कि महज वही

उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र होंगे, जिन्होंने मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाओं में 75 फीसद से अधिक अंक अर्जित किए हैं।

सरकार की पहली वर्षगांठ पर एक लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे – सीएम

राजस्थान, एजेसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर एक लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने सहित अनेक कदम उठाए जाएंगे जिनमें पालनहार योजना में पांच लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करना भी शामिल है। आधिकारिक बयान के अनुसार, शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार 'आपणो अग्रणी राजस्थान' की दिशा में निरंतर बढ़ते हुए अपनी पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें देकर उनका सशक्तीकरण करेगी। उन्होंने कहा कि दिसम्बर में वर्षगांठ के अवसर पर भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही दो हजार दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरित की जाएंगी और प्रत्येक जिले में कैम्प लगाकर 10 हजार दिव्यांग जनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग पांच लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित भी की जाएगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में एक लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी जिससे महिलाओं की उद्यम शीलता बढ़ेगी और वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगी।

संपादकीय

वक्फ के नाम पर लूट की खुली छूट

पता नहीं ट्रेन और बस की सीट पर रुमाल, बैग आदि रखकर उस पर अपना दावा करने का चलन आज भी है या नहीं, लेकिन यह पता चल गया कि वक्फ बोर्ड आज भी ऐसा कर रहे हैं। वे जिस जमीन–संपत्ति को चाहते हैं, उस पर नोटिस भेजकर अपना दावा जता देते हैं। इसका ताजा प्रमाण तब फिर मिला, जब कर्नाटक के विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर आदि जिलों के किसानों को नोटिस भेजकर कहा गया कि उनकी जमीन अब वक्फ की संपत्ति है। नोटिस भेजे जाने के साथ ही जब किसानों की जमीन का मालिकाना हक बदलने का काम शुरू होने की खबर आई तो उनमें हड़कंप मचा। उन्होंने पक्ष–विपक्ष के नेताओं से गुहार लगानी शुरू की और इस तरह वक्फ बोर्ड की मनमानी का मामला सामने आया। यह मनमानी किस हद तक थी, इसका पता इससे चलता है कि अकेले विजयपुरा जिले के होनावदा गांव के किसानों को नोटिस भेजकर उनकी 1,500 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति बता दिया गया। जब भाजपा ने इस मामले को तूल दिया तो सरकार हरकत में आई और खुद मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने कहा कि किसानों को भेजे गए नोटिस वापस लिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की ओर से यह तो कहा गया कि अधिकारियों की गलती से किसानों को नोटिस चले गए, लेकिन इसके बारे में कोई खबर नहीं कि जिनकी गलती से हजारों किसानों की जमीन को वक्फ की जमीन करार देने के नोटिस जारी किए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से यह भी सफाई दी गई कि होनावदा गांव में केवल 11 एकड़ जमीन वक्फ की है, शेष किसानों की है, लेकिन किसानों का कहना है कि इस 11 एकड़ में से भी 10 एकड़ जमीन तो वह है, जहां वह अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। उनका कहना है कि क्या हम अपने खेतों से हाथ धोने के बाद चौन से मर भी नहीं सकते। आरोप है कि वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने वक्फ अधिनियम में बदलाव की पहल को देखते हुए हजारों किसानों को आनन–फानन नोटिस भेजकर उनकी जमीन को वक्फ की जमीन करार देने का काम कराया। उनके अधीन काम करने वालों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने मुस्लिम किसानों को भी नोटिस भेज दिए। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण वाली कई ऐतिहासिक इमारतों को भी वक्फ संपत्ति घोषित करने के नोटिस जारी किए गए। यह पहली बार नहीं है, जब किसी राज्य के वक्फ बोर्ड ने मनमाने तरीके से किसी अन्य की जमीन, भवन आदि को वक्फ की संपत्ति करार दिया हो। तमिलनाडु के उस मामले से हर कोई परिचित होगा, जिसमें एक गांव की लगभग पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंथुरई गांव में एक 1,500 साल पुराना मंदिर है। कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि मंदिर और उसके आसपास की सारी जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड के पास अपने इस दावे के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसने नोटिस जारी कर करीब–करीब पूरे गांव पर अपना दावा कर दिया। गांव के लोगों को वक्फ बोर्ड की मनमानी का पता तब चला, जब एक किसान ने अपनी जमीन बेचने की पहल की। जब इस मामले की जांच हुई तो वक्फ बोर्ड का दावा फर्जी पाया गया। जांच में यह भी पता चला कि वक्फ बोर्ड ने फर्जी दस्तावेज बना रखे थे। वक्फ बोर्ड की कलई खोलने का काम 1,500 साल पुराने मंदिर के शिलालेख ने भी किया। यह सनद रहे कि 1,500 साल पहले इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था और वह भारत तो बहुत बाद में आया।

हाल के समय में वक्फ बोर्डों की मनमानी के कई उदाहरण आ चुके हैं। ये दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में देखने को मिले हैं। इसके बाद भी वक्फ अधिनियम में संशोधन की पहल का विरोध हो रहा है। यह विरोध मुस्लिम समुदाय के मजहबी नेता तो कर ही रहे हैं, अधिसंख्य विपक्षी दलों के नेता भी कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं की मानें तो मौजूदा वक्फ अधिनियम में कहीं कोई खामी नहीं और इसलिए उसमें किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो क्या वे वक्फ अधिनियम की तर्ज पर किसी सनातन भू अधिनियम की पैरवी करेंगे, ताकि हिंदू समुदाय भी अपने मठ, मंदिरों और उनकी जमीनों की रक्षा कर सके और उनका नियमन कर सके? न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि सभी समुदायों के लिए वैसा ही अधिनियम होना चाहिए, जैसा मुस्लिम समाज के लिए वक्फ अधिनियम है। केंद्र सरकार की ओर से मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन की जो पहल की जा रही है और जिस पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी विचार कर रही है, उसके कामकाज से विपक्षी सांसद बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। इसी कारण जेपीसी की बैठकों में हंगामा हो रहा है। जेपीसी अध्यक्ष के रवैये से विपक्षी सदस्य इतने खफा हैं कि वे उसका बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। पता नहीं उनकी आपत्ति क्या है, लेकिन यदि वे कर्नाटक के विजयपुरा जिले का मामला सामने आने के बाद भी यह चाहते हैं कि वक्फ कानून में किसी तरह का संशोधन–परिवर्तन न हो तो यह स्वीकार नहीं हो सकता। देश जानबूझकर जीती मक्खी नहीं निगल सकता। इससे इन्कार करना खुद को और साथ ही देश को जानबूझकर धोखा देना है कि मौजूदा वक्फ कानून में किसी बदलाव की जरूरत नहीं। इस कानून में ऐसे बदलाव किए ही जाने चाहिए, जिससे एक ओर जहां वक्फ बोर्ड मनमानी न कर सकें, वहीं दूसरी ओर वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग थमे।

टीम ट्रम्प ने अपने लिए जो रोडमैप तैयार किया

विनोद

डोनाल्ड ट्रम्प का राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना जाना अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी वापसी में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। ट्रम्प ने एक ऐसे अभियान पर विजय प्राप्त की, जिसमें उन्हें फासीवादी, जेनोफोब, महिला–द्वेषी और दोषी अपराधी के रूप में दर्शाया गया था। यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि, एक विभाजनकारी अभियान के बाद, वह संभवतः लोकप्रिय वोट का बहुमत हासिल कर रहे हैं। ट्रम्प की जीत, रिपब्लिकन द्वारा सीनेट पर फिर से कब्जा करने और प्रतिनिधि सभा को बनाए रखने की संभावना से बल पाकर, उन्हें अपने अभियान भाषणों में उभरे रूढ़िवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस जनादेश देती है, लेकिन उनके करीबी सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए नीति दस्तावेजों में अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है, जिनमें प्रोजेक्ट 2025 भी शामिल है। अमेरिका के परिणाम हाल के वर्षों में यूरोप में स्पष्ट रूप से देखे गए रुझानों के साथ मेल खाते हैं, जहाँ आबादी का बढ़ता अनुपात, उदार नीतियों द्वारा उन्हें ले जाई जा रही आर्थिक और सामाजिक दिशाओं से नाखुश, उन पार्टियों को वोट दे रहा है, जिन्हें मुख्यधारा के समूह दक्षिणपंथी और फासीवादी के रूप में बहिष्कृत करते हैं। नई ट्रम्पियन रिपब्लिकन विचारधारा का उदय यूरोप में दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, कुछ अलोकतांत्रिक तरीकों को कम कर सकता है जिनका उपयोग ऐसे दलों को शासन से बाहर रखने के लिए किया गया है। ट्रम्प के एजेंडे में अमेरिका के जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित दोहन, अमेरिका में और अधिक उद्योगों को वापस लाना, देश के गैर–औद्योगिक भागों में लाखों नौकरियां पैदा करना और ईंधन की कीमतों को कम करना शामिल है। इसमें टैरिफ में भारी वृद्धि शामिल है – व्यापार भागीदारों को अपने टैरिफ कम करने के लिए प्रेरित करने और अमेरिका में उद्योग स्थापित करने और आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। व्यापार को प्रोत्साहन के रूप में कर कटौती ट्रम्प का एक निरंतर मंत्र रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए इन उपायों को क्रमबद्ध करना कि मुद्रास्फीति न बढ़े, कीमतों में अत्यधिक उतार–चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान न हो, और राजकोषीय घाटा तेजी से न बढ़े, एक बड़ी चुनौती होगी। अभी तक, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह कैसे किया जाएगा। बाहरी तौर पर, किए गए सभी बेतुके दावों के बावजूद, दुनिया के प्रति ट्रम्प का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। वह इस तथ्य से अवगत हैं कि अमेरिका आज एक अति–विस्तारित महाशक्ति है। वे युद्धों में अमेरिका की भागीदारी और अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतारने के खिलाफ हैं, सिवाय इसके कि वित्तीय रूप से जिम्मेदार तरीके से अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए – और हमेशा यह ध्यान में रखते हुए कि मुख्य रणनीतिक विरोधी चीन है। जहां अमेरिका और उसके सहयोगी संयुक्त रूप से सुरक्षा हितों की रक्षा में शामिल हैं, सहयोगियों को अपने हिस्से का बोझ उठाना चाहिए। अपने अभियान के दावे को एक तरफ रखते हुए कि वे यूक्रेन संघर्ष को रातोंरात हल कर देंगे, उनका दीर्घकालिक दृष्टिकोण यह है कि यूरोप और रूस को यूरेशियन सुरक्षा वास्तुकला पर काम करना चाहिए। यूरोपीय नाटो सहयोगियों को आगे आना चाहिए और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, ताकि वे एक व्यवहार्य पारंपरिक निवारक का निर्माण कर सकें, जबकि अमेरिका एक परमाणु छत्र के साथ आगे बढ़े। इससे अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक परिसर को एक स्थिर व्यावसायिक धारा मिल सकती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रम्प पश्चिम एशियाई युद्ध से कैसे निपटेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए उनका दृढ़ समर्थन निश्चित रूप से उन्हें बिडेन प्रशासन की तुलना में बेहतर लाभ देगा। अब्राहम समझौते के साथ शुरू की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए इसका फायदा उठाना उनकी सौदेबाजी क्षमताओं का एक कठिन परीक्षण होगा। अपने अभियान के दौरान ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गर्मजोशी से बात की है। यह दोनों देशों में भारत के साथ मजबूत संबंधों के लिए अमेरिका में द्विदलीय समर्थन के सार्वजनिक बयानों के अनुरूप है। इस समर्थन का रणनीतिक आधार यह है कि एशिया में एक लोकतांत्रिक भारत, जो रणनीतिक रूप से चीन के बगल में और हिंद महासागर में स्थित है, इंडो–पैसिफिक में अमेरिकी आर्थिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में एक मूल्यवान भागीदार होगा। भारत ने इस रणनीतिक हित का प्रतिदान किया है। रक्षा बिक्री, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार में उछाल ने इन संबंधों को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में संबंधों की गुणवत्ता में बदलाव आया है। जैसा कि हाल ही में एक अमेरिकी रणनीतिक विश्लेषक ने बताया, बुश प्रशासन के दौरान संबंधों के प्रति अमेरिकी रवैया रणनीतिक परोपकारिता का था – दक्षिण एशिया में एक मजबूत, लोकतांत्रिक भारत अमेरिका के लिए पर्याप्त संपत्ति थी, बिना अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत को अन्य संबंधों से रोके। बिडेन प्रशासन के तत्व रूस और चीन के बारे में अपने स्वयं के साथ अधिक संरेखित स्थिति के साथ अमेरिकी समर्थन का प्रतिदान न करने के लिए भारत की अधिक आलोचना कर रहे हैं। इससे हाल के महीनों में कुछ असंगत अभिव्यक्तियाँ सामने आई हैं। सार्वजनिक बयानों और कार्रवाइयों ने – अक्सर कनाडा के साथ मिलकर – न केवल खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर मतभेदों को राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचा दिया है, बल्कि इसमें कठोर सार्वजनिक दावे भी शामिल हैं कि जवाबदेही का लगातार पीछा किया जाएगा च्चाहे सत्ता से निकटता हो या न होष्। इससे जुड़ा एक उदाहरण व्हाइट हाउस का है जिसने खालिस्तान समर्थक प्रतिनिधियों के एक समूह को सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन देने के लिए आमंत्रित किया कि मोदी के उस दिन अपनी धरती पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय आक्रमण से सुरक्षा दी जाएगी।

हर किसी के लिए असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा

राहुल

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज कुचल दी थी। यह आवाज

अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। कंपनी ने हमारे राजा–महाराजाओं और नवाबों की साझेदारी से, उन्हें रिश्वत देकर और धमका कर भारत पर शासन किया था। उसने हमारी बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित कर लिया था। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथों नहीं गंवाई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया, जो हमारे देश में दमन तंत्र को चलाता था। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी। वही यह तय करने लगी कि कौन क्या और किसे बेच सकता है। कंपनी ने हमारे कपड़ा उद्योग और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को भी नष्ट कर दिया था। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी द्वारा कभी कोई अनुसंधान किया गया। मुझे बस इतना पता है कि कंपनी ने एक क्षेत्र में अफीम की खेती पर एकाधिकार हासिल कर लिया था और दूसरे में नशा करने वालों का एक बाजार विकसित कर लिया था। जब कंपनी भारत को लूट रही थी, तब उसे ब्रिटेन में एक आदर्श कारपोरेट निकाय के रूप में दर्शाया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही सैकड़ों साल पहले खत्म हो गई हो, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था, वह आज फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने इसकी जगह ले ली है। परिणामस्वरूप जहां भारत में हर किसी के लिए असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा है, वहीं यह वर्ग अकूत धन एकत्रित करने में लगा है। हमारी संस्थाएं अब हमारे लोगों की नहीं रहीं। वे एकाधिकारवादियों के आदेश मानती हैं। आज लाखों व्यवसाय तबाह हो गए हैं और भारत युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में असमर्थ है। भारत माता अपने सभी बच्चों की मां है। उसके संसाधनों और शक्ति पर कुछ चुनिंदा लोगों के एकाधिकार और बहुजनों की उपेक्षा ने गहरी चोट पहुंचाई है। मैं जानता हूं कि भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली और अग्रणी व्यवसायी एकाधिकारवादियों से डरते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं, जो फोन पर बात करने से डरते हैं? क्या आप आयकर, सीबीआइ या ईडी के छापों का सामना करने से डरते हैं कि वे आपको अपना व्यवसाय बेचने के लिए मजबूर करेंगे? क्या आपको डर है कि जब आपको सबसे अधिक जरूरत हो, तब वे आपको पाई–पाई का मोहताज कर देंगे या वे आपको फंसाने के लिए अनायास ही नियम बदल देंगे? इन पारिवारिक समूहों को 'व्यवसाय' की संज्ञा देना गलत है। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना किसी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। उनकी मूल क्षमता उत्पादों, उपभोक्ताओं या विचारों में नहीं, बल्कि भारत की शासकीय संस्थाओं, नियामकों और निगरानी पर नियंत्रण रखने की है। ये नियंत्रित करते हैं कि भारतीय क्या पढ़ते, देखते, सोचते और कहते हैं। आज सफलता का निर्धारण बाजार में प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि सत्ता से संबंधों पर निर्धारित है। आपके दिलों में डर है, लेकिन उम्मीद भी कायम है। 'मैच–फिक्सिंग' करने वाले एकाधिकार समूहों के विपरीत छोटे व्यवसायों से लेकर दिग्गज कंपनियों तक कई अद्भुत और ईमानदार भारतीय व्यवसाय हैं, लेकिन आप चुप हैं और एक दमनकारी व्यवस्था को सहन कर रहे हैं। पीयूष बंसल ने महज 22 साल की उम्र में व्यवसाय शुरू किया। वह 2010 में लेंसकार्ट की स्थापना से जुड़े, जिसने आईवियर सेक्टर को भारत में नया आकार दिया, जो आज हजारों लोगों को रोजगार देता है। हमारे सामने फकीर चंद कोहली की भी मिसाल है, जिन्होंने एक प्रबंधक के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बुनियाद रखी। यह डर पर महत्वाकांक्षा की जीत थी और आइबीएम एवं एक्सेंचर जैसी दिग्गजों को उनके अपने क्षेत्र में चुनौती देने का साहस था। मैं पीयूष बंसल या दिवंगत एफसी कोहली को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं मेरी पसंद से अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? युवा पीढ़ी से टाइनोर, इनमोबी, मान्यवर, जोमैटो, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, अराकू काफी, ट्रेडेंस, अमागी, आइडी फूड्स, फोनपे, मोग्लिक्स, सुला वाइन, जसपे, जीरोधा, वेरिटास, आक्सीजो और एवेंडस जैसी कंपनियां और पुरानी पीढ़ी से एलएंडटी, हल्दीराम, अरविंद आई हास्पिटल, इंडिगो, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी समूह, बजाज आटो और बजाज फाइनेंस, सिप्ला, महिंद्रा आटो एवं टाइटन आदि ऐसी घरेलू कंपनियों के उदाहरण हैं, जिन्होंने अनुसंधान किया और नियमों के अनुसार काम करना चुना। मुझे यकीन है कि मैंने सैकड़ों और कंपनियों को छोड़ दिया है, जो इन मापदंडों पर उपयुक्त बैठती हैं, लेकिन आप बात समझ गए होंगे। मेरी राजनीति हमेशा कमजोर और बेजुबान लोगों की हिफाजत की रही है। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की रक्षा के बारे में महात्मा गांधी के शब्द ही मेरी प्रेरणा हैं। मुझे मनरेगा एवं भोजन के अधिकार का समर्थन करने और भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने की प्रेरणा इसी से मिली। मैं आदिवासियों के मशहूर नियमगिरि के संघर्ष में उनके साथ खड़ा था। मैंने तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष में उनका समर्थन किया। मैंने मणिपुर के लोगों के दिल का दर्द सुना। व्यापार की जिस पंक्ति में आप खड़े हैं, उसमें आप ही शोषित, वंचित हैं और इसलिए मेरी राजनीति का लक्ष्य अब आपको वह सब दिलाना है, जिससे आपको वंचित किया गया है यानी निष्पक्षता एवं समान अवसर दिलाना। सरकार को दूसरों की कीमत पर बस एक व्यवसाय का समर्थन करने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। सरकारी एजेंसियां व्यापार पर हमला करने और डराने–धमकाने का हथियार नहीं हैं। मेरा मतलब यह नहीं कि जो डर और दबाव आप पर बनाया गया है, वह बड़े पूंजीपतियों पर ट्रांसफर किया जाए। वे बुरे लोग नहीं हैं। उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए जैसे आपको भी। यह देश हम सभी के लिए है। हमारे बैंकों को सबसे बड़े 100 प्रभावशाली कर्जदारों और उनके एनपीए के प्रति अपने मोह को छोड़कर लाभदायक कर्ज देने और निष्पक्ष व्यापार को समर्थन देने वाले तौर–तरीकों की खोज करनी चाहिए। हमें राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में सामाजिक दबाव और प्रतिरोध की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मसीहाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद वह बदलाव हैं, जो सभी के लिए धन और रोजगार पैदा करेंगे। मेरा मानना है कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए न्यू डील एक ऐसा सोच है, जिसका समय आ गया है।

अनचाहे गर्भ की सूची में शामिल करने वाले शोध

ललित

एक अध्ययन के निष्कर्ष, राष्ट्रव्यापी आंकड़ों से अनचाहे गर्भधारण की पहली जिला–स्तरीय जांच, खुलासा करने वाले और महत्वपूर्ण हैं। बीएमसी प्रेग्नेंसी एंड चाइल्डबर्थ पत्रिका में प्रकाशित इस शोध से पता चला है कि भारत के 82 जिलों में अनचाहे गर्भधारण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बंगाल के तीन जिले – बीरभूम, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर – इन हॉट स्पॉट में शामिल हैं, जैसे कि बिहार में 30 जिले, उत्तर प्रदेश में 14, मध्य प्रदेश में 8, दिल्ली में 6, हरियाणा में 4 और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3–3 जिले हैं। क्षेत्रीय विविधताएं दिलचस्प सवाल खड़े करती हैं। भारत के उत्तरी राज्य, कम साक्षरता के संयोजन के लिए जाने जाते हैं – बिहार की साक्षरता दर 61.7% है जबकि उत्तर प्रदेश की 73% है – रूढ़िवादी सामाजिक मानदंड, और महिलाओं के लिए कम व्यक्तिगत एजेंसी, सामाजिक कारकों का एक शक्तिशाली कॉकटेल पेश करते हैं लेकिन केरल और दिल्ली, शिक्षित, शहरी, आर्थिक केंद्र, जिनसे ऐसी प्रतिगामी प्रवृत्तियों को रोकने की उम्मीद की गई थी, वे भी खुद को ऐसे भौगोलिक समूहों में पाते हैं, जहाँ अनचाहे गर्भधारण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च आय और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच जैसे जनसांख्यिकीय संकेतक हमेशा महिलाओं के जीवन, विकल्पों या उनके शरीर पर उनके अधिकार को सुरक्षित नहीं करते हैं। एक लड़के के लिए सांस्कृतिक वरीयता प्रगति की ताकतों के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनी हुई है, यहाँ तक कि अपेक्षाकृत समृद्ध शहरी भूगोल में भी।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्यापक संस्कृति को देखते हुए, यह पूछना भी उचित है कि क्या जिन महिलाओं का गर्भधारण यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों का परिणाम है, उन्हें अपने साथियों की तरह ही स्वास्थ्य सेवा और सहायता प्राप्त होती है। इस अध्ययन से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देने – उन्हें खत्म करने – के अलावा अन्य उपयोगों में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जो जानकारी सामने आई है, वह नीति को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है जहाँ गर्भनिरोधक का उपयोग कम है और फिर समस्या का समाधान कर सकती है। आगे के शोध के भविष्य के पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए डेटा की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह तथ्य कि केरल के 14 में से आठ जिलों में अनचाहे गर्भधारण की उच्च प्रवृत्ति दिखती है, इस बारे में अनुवर्ती प्रश्नों को जन्म दे सकता है कि सर्वश्रेष्ठ मातृ एवं शिशु देखभाल सूचकांक वाला राज्य अवांछनीय गर्भधारण को रोकने में विफल क्यों रहा है। इस दिशा में भविष्य की शोध परियोजनाओं के लिए संसाधन और जनशक्ति बाधा नहीं होनी चाहिए। उत्तरों का राष्ट्रीय कल्याण पर असर होगा।

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे से करवट लेगी राजनीति

संजय

सभी की निगाहें 23 नवंबर पर टिकी हैं, जब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। नतीजे इस बात का संकेत होंगे कि आने वाले महीनों और सालों में इस देश की राजनीति किस करवट बैठेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा में अप्रत्याशित हैट्रिक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बूस्टर डोज मिल गई है, जिसमें अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस ने हार मान ली है। महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा द्वारा क्लीन स्वीप किए जाने से विपक्ष फिर से असहाय हो जाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बात का जवाब तलाश रहे होंगे कि आखिर कहां गलती हुई। विपक्षी हलकों में यह भावना कि अब मोदी के अतीत की बात हो जाने का समय आ गया है, निराशा में बदल जाएगी। विपक्ष का भारत गुट ताजा हवा के लिए हांफेगा। भारत गुट के भीतर आंतरिक गतिशीलता ऐसी है

कि सभी गैर–कांग्रेसी दलों को लगता है कि यह सबसे पुरानी पार्टी है और हर संभव अवसर पर उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। भाजपा के लिए यह उचित है कि वह इस तरह के प्रयास में अनौपचारिक रूप से उनकी मदद करे। परेशान कांग्रेस एकता का मंत्र तो जपती रहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अपने सहयोगियों को कैसे खुश रखा जाए। अगले साल, केवल दो विधानसभा चुनाव होने हैंरू एक दिल्ली में साल की शुरुआत में और दूसरा बिहार में, जो साल के अंत में होने वाला है। मोदी, जो पहली बार लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रहे हैं, के सामने एक परीक्षा है। उन्हें इस महीने यह दिखाना होगा कि संसदीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन न करना एक अपवाद था और वे जीत की राह पर लौट आए हैं। झारखंड में, भाजपा को लगता है कि उसके पास एक विजयी गठबंधन है, और राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया समूह के खिलाफ संघर्ष में चिंता की कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनावों में विपक्ष द्वारा की गई गहरी पैठ के साथ महाराष्ट्र को हराना मुश्किल लग रहा है। इससे भी अधिक कठोर तथ्य यह है कि 48 लोकसभा सीटों में से 31 पर विपक्ष की जीत प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत झटका से कहीं अधिक थी। भाजपा के स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे महाराष्ट्र में घूमे थे और 18 रैलियों को संबोधित किया था, लेकिन भाजपा के वर्चस्व वाली महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिलीं, जो पिछली बार की 41 सीटों से 20 से ज्यादा कम है। यह ब्रांड मोदी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति का स्पष्ट खंडन था। अगर लड़की बहन योजना समेत आखिरी समय में की गई बड़ी–बड़ी सौगातों को छोड़ दिया जाए, तो एकनाथ शिंदे सरकार ने शासन के मुद्दे पर बहुत कम काम किया है। और अगर विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने अपनी रणनीति बनाई, तो यह सत्तारूढ़ पक्ष के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। मोदी–शाह की जोड़ी विपक्षी वोटों को विभाजित करने के लिए हर संभव चाल चल रही है और ऐसा करने के लिए उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। महा विकास अघाड़ी में सीटों के आवंटन को अंतिम रूप देने में देखी गई परेशानियाँ विपक्षी समूह में खींचतान और दबाव के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, जिसे लगता है कि उसके पास जीतने के लिए बहुत ज्यादा मौके हैं। सही हो या गलत, राज्य के राजनीतिक हलकों में यह धारणा है कि विपक्षी महा विकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और सत्तारूढ़ महायुति में अजित पवार की एनसीपी कई कारणों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। उद्धव ठाकरे भले ही जोरदार वक्ता हों, लेकिन वोट कांग्रेस के पास है। भतीजे को काबू में रखने के लिए शरद पवार के सितारे बुलंदियों पर हैं और मराठा दिग्गज छोटे स्तर पर भी रणनीति बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस और भाजपा, साथ ही शरद पवार की एनसीपी भी उद्धव और उनकी पार्टी को रोकने की कोशिश में एक ही पन्ने पर हैं। राज ठाकरे के साथ–साथ प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी और कई अन्य छोटे खिलाड़ियों द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की योजना को सत्तारूढ़ पक्ष की कुशलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो विपक्ष के वोट में सेंधा लगाना चाहता है। "वोट कटवा" की बहुत मांग है। ऐसा कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई भी ऐसे कई खिलाड़ियों को "सही" रास्ते पर रखने में मदद कर रहे हैं। राज्य में भाजपा के शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौती यह है कि महायुति के वोटों में 25 लाख की वृद्धि करके एमवीए को परेशान किया जाए। लड़ाई को सिर्फ 25 लाख वोटों तक सीमित करना यह दिखाने का एक तरीका है कि लड़ाई सिर्फ बच्चों का खेल है। महाराष्ट्र के नतीजों का राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा। यह तय करेगा कि नरेंद्र मोदी फिर से अपने मालिक हैं या नहीं। हरियाणा की हैट्रिक ने उन्हें लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद संयम हासिल करने में मदद की है। लेकिन हरियाणा को सिर्फ एक अपवाद के रूप में देखा जाता है। इसलिए, यह दिखाने के लिए कि वे आखिरकार पहुँच गए हैं, श्री मोदी को यह दिखाना होगा कि उन्होंने देश के सबसे धनी राज्य महाराष्ट्र में जीत हासिल की है। अगर वह इसे आसानी से हासिल कर लेते हैं, तो उनका कद बढ़ेगा। और नकारात्मक लोग या श्रीमान संदेहवादी उनके साथ आ जाएंगे।

भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रदेश के सभी जिलों में 15 से 26 नवम्बर तक मनाया जायेगा - मुकेश मेश्राम

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, पर्यटन विभाग, जनजातीय विकास विभाग, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा इफको नई दिल्ली एवं उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में बिरसा मुण्डा जी की जयन्ती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन 15 से 20 नवम्बर, 2024 तक उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर लखनऊ के परिसर में किया जायेगा।

यह जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को आज पर्यटन भवन में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मेश्राम तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण डा0 हरिओम ने दी। दोनों अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, समाज कल्याण विभाग तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली व इफको टोकियो इस कार्यक्रम के प्रायोजक रहेंगे।

प्रेस कान्फ्रेंस में प्रमुख सचिव पर्यटन ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी उत्सव में गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरूणांचल प्रदेश, गोवा, केरल, हिमांचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब तथा उ0प्र0 सहित 22 राज्यों के 600 से अधिक कलाकार अपने पारम्परिक नृत्य, संगीत, परिधान, वादयंत्रों का प्रदर्शन करेंगे।

श्री मेश्राम ने बताया कि इस आयोजन में हस्त शिल्प के 100 से अधिक स्टॉल लगाये जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड से इम्ब्रायडरी, हैंडलूम चादर, मध्य प्रदेश से बीडज्वैलरी, लेदरशिल्प, चंदेरी साड़ी तथा उ0प्र0 से खुर्दा पाट्री, ब्रास वर्क, बनारसी साड़ी, सुपारी के खिलौने तथा गाय के गोबर से बने उत्पाद व प्रधानमंत्री वनधन केन्द्रों में निर्मित उत्पाद आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। आयोजन में देशी व्यंजन के स्टॉल भी लगाये जायेंगे। इस उत्सव में स्लोवाकिया तथा वियतनाम के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है।

प्रमुख सचिव समाज कल्याण डा0 हरिओम ने बताया कि वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा लोक नायक बिरसा मुण्डा के जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसके आयोजन हेतु सभी जिलों में 15 से 26 नवम्बर, 2024 तक जनजाति गौरव पखवाड़ा मनाया जायेगा, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर, 2024 को प्रारम्भ किये गये ''धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान'' के तहत प्रदेश के 517 जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस अवसर पर हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया।

डा0 हरिओम ने बताया कि इस अवधि में 22 राज्य, 38 लोकनृत्य प्रस्तुत करेंगे। इस आयोजन में शिल्प मेला, चाय चौपाल, पारम्परिक देशी खेल, पोथी घर जनजाति पुस्तकों की बिक्री आदि भी की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य देश की जनजातीय लोक परम्परा, लोक गायन, समृद्ध गौरवशाली इतिहास, भेष–भूषा व्यंजन तथा पारम्परिक मूल्यों से भावी पीढ़ी को परिचित कराया जा सके ताकि आज की युवा पीढ़ी अपनी समृद्धशाली विरासत पर गौरव महसूस कर सके। इस अवसर पर विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया एवं लोक जनजाति संस्थान के अध्यक्ष अतुल द्विवेदी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

विकास खंड माल ब्लाक की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ संपन्न

मृत्युंजय प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा लखनऊ की ब्लाक कार्यकारिणी 2024–25 माल ब्लॉक का द्विवार्षिक चुनावी अधिवेशन आज दिनांक रू–8ध्11ध्2024 को पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विकासखंड माल में संघ चुनाव अधिकारी –श्री मयंक धजिला मंत्री,उनके साथ रहे सह चुनाव अधिकारी नरेंद्र कुमार द्वारा कुल 05 पदों पर नामांकन प्रक्रिया संपन्न करायी गयी जिसमें अन्य किसी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन न किये जानें पर सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए । इस प्रकार अध्यक्ष पद पर– श्री जगन्नाथ प्रसाद , ब्लॉक मंत्री पद पर श्री राम मिलन , ब्लॉक कोषाध्यक्ष पद पर श्री विनय कुमार, संगठन मंत्री पद पर श्री तेज प्रकाश ,एवं ब्लॉक संप्रेक्षक पद पर श्री जगदीश सिंह (निर्विरोध) निर्वाचित हुए। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को संघ चुनाव अधिकारीधजिला मंत्री (श्री मयंक) द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के साथ ही पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई । इस प्रकार विकास खंड माल की निर्वाचन प्रक्रिया समस्त कर्मचारी की उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल सम्पन्न हुई। चुनावी प्रक्रिया संघ के जिला अध्यक्ष राम किशन के निर्देशों के क्रम में संपन्न कराई गई। सभी नव निर्वाचित ब्लाक पदाधिकारियों को संघ के (जिला अध्यक्ष – रामकिशन) (जिला मंत्री – मयंक)(जिला कोषाध्यक्ष – धर्म प्रकाश कुशवाहा) जिला संगठन मंत्री मनोज भारती (जिला संप्रेक्षक– श्री भगवान, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष वेद प्रकाश (जिला कार्यवाहक अध्यक्षध्मंडल अध्यक्ष पवन वाल्मीकि)(मंडल मंत्री प्रवीण भारती) (जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू भारती) जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार, जिला संयुक्त मंत्री संदीप कुमार, जिला उपाध्यक्ष सनी सिंह , जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गौतम एवं जिला उपाध्यक्ष शिवराज सहित समस्त जिला कार्यकारिणी ने जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

नौ मिनट में थ्रीडी इफेक्ट के जरिये राम वन गमन मार्ग का दर्शन करा रहा है दुर्लभ दर्शन केन्द्र

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। सरकार रामनगरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने मे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।देश–विदेश से अयोध्या आने वाले भक्तों को श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास के दौरान किये गए संघर्षों की गाथा थ्रीडी वीडियो के जरिये दिखाई जा रही है। सिर्फ 9 मिनट के वीडियो में ही श्रद्धालु श्रीराम के जीवन उतार चढ़ाव को देखकर भाव–विभोर हो जा रहे हैं। इसके लिए हनुमान गढ़ी के पास राज द्वार पार्क में दुर्लभ दर्शन केंद्र की स्थापना कराई गई है।बताते चले कि राम नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को श्रीराम के जीवन जुड़ी गाथाओं से लोगों को जोड़ने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से श्रीराम वन गमन से जुड़े वर्चुअल रियलिटी पर डेमो शुरू कराया है। काशी विश्वनाथ, मां वैष्णो देवी भवन में भी ऐसी व्यवस्था है। 9 मिनट में अयोध्या को एनिमेशन के जरिये दिखाया जाता है।इसमें तमसा नदी, भरत मिलाप, लक्ष्मण पहाड़ी, अनुसुइया माता दर्शन, दंडकारण्य, पंचवटी, धनुषकोडि, एनिमेशन के ही जरिये श्रीराम का लंका में सूर्य तिलक दिखाया जाता है।दुर्लभ दर्शन केंद्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। करार के तहत टेक

एक्स आर इनोवेशंस कंपनी ने अभी केंद्र में 10 कैमरे लगवाए हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को एक हेड फोन भी दिया जाता है। नगर क्षेत्र में और भी दुर्लभ दर्शन केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है। 18 तीर्थस्थलों को वर्चुअल रिएलिटी के जरिए जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए शूटिंग पूरी कर ली गई है। इसमें श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढ़ी मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पैड़ी, छोटी देवकाली मंदिर, रंग महल, सूर्य कुंड, भरत कुंड, गुप्तार घाट, बड़ी देवकाली मंदिर, कनक भवन मंदिर व दशरथ महल मंदिर मुख्य हैं।इस मौके पर राम नगरी मे बीकानेर से आये विकास तिवारी ने दुर्लभ दर्शन के बाद बताया कि गजब का अनुभव हुआ है। अयोध्या आने वाले हर भक्त को रामलला का दर्शन करने के पश्चात इसे जरूर देखना चाहिए।अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडेय ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी इस योजना बढ़ावा दिया गया है। हालांकि अभी यह डेमो के तौर पर दिखाया जा रहा है। अब तक एक हजार से भी अधिक लोग इसका डेमो ले चुके हैं। अभी इसके और केंद्र भी खोले जाएंगे। उज्जैन की भस्म आरती, मैहर, वैष्णो देवी व ओंकारेश्वर व भीमाशंकर के धार्मिक स्थलों व कथाओं को भी यहां दिखाने की कवायद शुरू की गई है।अयोध्या में अभी और दुर्लभ केंद्र खोले जाने हैं। अभी दीपोत्सव पर शुरू हुए दुर्लभ केंद्र का चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में 100 से 150 रुपये चार्ज लिया जाएगा। चार्ज के माध्यम से सरकार को भी राजस्व जाएगा।

राम नगरी में मनमानी पार्किंग शुल्क वसूली पर श्रद्धालुओ ने प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। अयोध्या में श्रद्धालुओं से अत्यधिक पार्किंग शुल्क वसूली का मामला गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में लता मंगेशकर पार्क के उत्तर दिशा में बने पार्किंग स्थल पर तीन घंटे के लिए 100 रुपये वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं।इस संबंध मे राम नगरी मे भारीतय संख्या मेरे दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इतनी महंगी पार्किंग दर से धार्मिक यात्रा उनके लिए भारी पड़ रही है। इसके साथ ही साथ उनके भक्ति भाव पर नकारात्मक असर डाल रही है।आरोप लगाया जा रहा है कि पार्किंग स्थल का ठेकेदार मनमाने तरीके से शुल्क वसूल रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप से कतराया जा रहा है।

ठेकेदार की ऊंची पहुंच और प्रभाव के कारण स्थानीय अधिकारी भी इस मामले में संज्ञान लेने से बच रहे हैं। इस स्थिति ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों में असंतोष उत्पन्न कर दिया है। अयोध्या जैसे पवित्र शहर, जहां देश–विदेश से लाखों श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ आते हैं, में इस प्रकार की गतिविधियाँ शहर की छवि को धूमिल कर रही हैं। तीर्थयात्री अपने वाहन सुरक्षित पार्क करने के उद्देश्य से पार्किंग सुविधा का सहारा लेते हैं, लेकिन इस तरह के अतिरिक्त शुल्क से उनके बजट पर असर पड़ता है और वे असहज महसूस कर रहे हैं। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वह इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और पार्किंग शुल्क को नियंत्रण में रखे, ताकि धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं के अनुभव को सहज बनाया जा सके।

शहर के अधिकतर होटल व रेस्टोरेंट सहित ठेलों पर खुलेआम हो रहा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग

अयोध्या। शहर के अधिकतर रेस्टोरेंट, होटल,ठेलो व अन्य प्रतिष्ठनो पर घरेलू सिलेंडरो का संचालकों द्वारा जोर शोर से उपयोग किया जा रहा है।यहां तक कि सभी जगहों पर बिना रोकटोक व भय के घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।बताते चले कि अभी कुछ वर्षों पूर्व कोतवाली नगर क्षेत्र के देवकाली क्षेत्र में एक दुकान पर उस समय विस्फोट हो गया था जब उस दुकान का मालिक घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भर रहा था।उस समय तो जिला पूर्ति विभाग,फायर विभाग,पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कई प्रतिष्ठानो पर कार्यवाई किया था।परंतु संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी चुप्पी साधकर किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं।अभी कुछ दिनों पूर्व दीपावली के समय खाना पूर्ति कर रहे खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ एसडीएम सदर ने कुछ रेस्टोरेंट पर छापा मारा था।जिसमें कोतवाली नगर क्षेत्र मे ठीक सीओ सिटी ऑफिस के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया। जिसको लेकर कोतवाली नगर क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करा कर थाना पूर्ति कर लिया।अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिया जाए सिर्फ कोतवाली नगर क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में स्थित चाहे छोटा रेस्टोरेंट हो या फिर होटल,ठेले ही क्यों न हो सभी जगहों पर संचालको द्वारा घरेलू गैस का उपयोग करते हुए पाया जा रहा है।जिस पर जिला आपूर्ति विभाग के साथ–साथ अग्निशमन विभाग के अलावा पुलिस,खाद्य विभाग ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे है।कोतवाली नगर क्षेत्र के रिकाबगंज,चौक नियांवा, सिविल लाइन, देवकाली, बेनीगंज, अमानीगंज, रीडगंज, नाका शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां पर स्थित रेस्टोरेंट अथवा होटल के साथ–साथ ठेलों पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए ना पाया जाए।अगर देखा जाए तो जिला आपूर्ति कार्यालय के मानक के अनुसार किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान चाहे वह होटल हो रेस्टोरेंट हो यहां तक ठेले ही क्यों ना हो व्यावसायिक सिलेंडरों का उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इस प्रतिष्ठान के लोग नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के कई दुकानों पर घरेलू सिलेंडरों से छोटी सिलेंडरों में गैस भरने का काम भी बड़े जोर–शोर से चल रहा है इससे सिर्फ विस्फोट का ही खतरा नहीं है बल्कि आए दिन विभिन्न गैस एजेंसी मे तैनात हाकर की मिलीभगत सेंड घरेलू सिलेंडरो सें संबंधित दुकानदार गैस भी निकाल लेते है। परंतु संबंधित विभाग आंखे उस समय खुलती है जब सिलेंडर सिलेंडर से कोई घटना घट जाती है।

नारसन ब्लॉक न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता प्रारंभ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

नारसन, हरिद्वार। नारसन ब्लॉक के न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 प्रतियोगिता का प्रारंभ 8 नवंबर से 9 नवंबर 2024 प्रारंभ हुई । यह प्रतियोगिता मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार कमलेश कुमार गुप्ता तथा खंड शिक्षा अधिकारी हरिद्वार मेराज अहमद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मिल्खा सिंह निदेशकअधिकारी कामेश्वर उनियाल के संरक्षण में संपन्न हुई। ब्लॉक खेल समन्वयक पवन ,राणा ने बताया की इस प्रतियोगिता में नारसन ब्लॉक के न्याय पंचायत नारसन, ।। खेलों के माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है=कविंद्र चौधरी ब्लॉक प्रमुख नारसन। मोहम्मदपुर, मंगलौर, लिबरहेरी , मुंडलाना, गधा रोना, ढंडेरा, लाठर देवा तथा मखदुमपुर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। न्याय पंचायत लाठर देवा हूण मैं मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नारसन कविंद्र चौधरी तथा

84 एनसीसी बटालियन के करनल रमेश कृष्णन ने उपस्थित होकर प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया की अवसर पर उनका स्वागत ग्राम प्रधान श्रीमती ममता के प्रतिनिधि अशोक चौधरी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रपाल ने अंग वस्त्र पहनकर किया। तथा मंच का संचालन वीर सिंह ने किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सरस्वती पर दीप प्रज्वलित किया। प्रतियोगिता के दौरान नोडल अधिकारी आर्यावर्त चौधरी , एकता वासुदेव, जितेंद्र पाल सिंह राठी, सरताज अहमद, आरएस वर्मा, संगीता पाल तथा चंद्रपाल। व्यायाम शिक्षक कुलदीप कुमार , ज्ञानेश्वर कुमार, सुभाष चंद्र,दिनेश बड़वाल, प्रशांत राठी, संदीप,मनीष कुमार, ठाठ सिंह, आलोक कुमार द्विवेदी, विवेक राठी गणेश रावत, सौरभ कुमार, एसएस राठौर, अरुण खरे रमारानी, खेल प्रेमी सुशील, मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स अकैडमी के प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल रहमान, मनोज कटारिया, सुशील कुमार हिमांशु, तुषार आदि ने उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया।

पराली एवं फसल अवशेष जलाने के नाम पर किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं – घनश्याम वर्मा

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। प्रदूषण के नाम पर किसानों को पराली एवं फसल अवशेष जलाने से रोकना तथा जुर्माना करना व सुविधाओं से वंचित रखना और प्रचार प्रसार हेतु सरकारी धन को बर्बाद करना किसी भी दशा में उचित नहीं है तुरंत रोक लगना चाहिए। और किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए अन्यथा प्रबल विरोध किया जाएगा। उक्त उदगार व्यक्त करते हुए भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार फैक्ट्रियों एवं वाहनों से 76% और घरेलू कार्यों से 11% तथा खेती से मात्र 8: ही प्रदूषण फैलता है जनपद अयोध्या में पराली जलाने से प्रदूषण का प्रतिशत शून्य के बराबर है क्योंकि जनपद अयोध्या के छोटे किसान हैं जो पराली न जलाकर अपने पशुओं को चारा खिलाने के रूप में प्रयोग करते हैं किसानों से अधिक लोग शहरों में कूड़ा जलाते हैं यदि शासन– प्रशासन स्वच्छ मन से प्रदूषण को समाप्त करना चाहता है तो फैक्ट्री में पर लगाम लगाये , घनश्याम वर्मा ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी पराली वाहन को फर्जी दौड़ा कर फर्जी बिलिग करके देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं जिस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए अधिकारियों द्वारा पराली जलाने पर दिमाग न लगाने के बजाय फैक्ट्रियों, खटारा रेल इंजन, खटारा बसों से हो रहे प्रदूषण पर रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए घनश्याम वर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि यदि पराली व फसल अवशेष जलाने के नाम पर किसानों को परेशान किया गया तो प्रबल विरोध किया जाएगा।

5 वर्ष पूर्व रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर हुई थी ठगी मामले मे कोर्ट के आदेश परिवार छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। 5 वर्ष पूर्व डेढ़ साल में रकम दोगुना होने का लालच देकर रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर हुई ठगी के मामले में अदालत के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।इस संबंध मे पीड़िता कोतवाली नगर के कन्धारी बाजार निवासी सरिता पत्नी हृदय मोहन का कहना है कि वर्ष 2019 में अयोध्या कोतवाली के रायगंज निकट राम श्याम होटल निवासी श्रीपति लाल और कौशलेश कुंज कॉलोनी, स्टेशन रोड निवासी राकेश गुप्ता ने लखनऊ स्थित रियल एस्टेट कंपनी में रकम लगाने पर 18 महीने में दो गुना होने तथा परिपक्व रकम अथवा लखनऊ में प्लाट दिलाने का वास्ता देकर 75 हजार रूपये का निवेश कराया था।आरोप के मुताबिक कंपनी की ओर से भुगतान न होने पर ब्याज सहित वापस करने की बात कही थी। तीन साल बाद रकम वापसी के लिए कहा तो आनाकानी शुरू हो गई। जिसके बाद उसने कंपनी के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि यह लोग वास्तुम इन्फ्रा प्रा. लि... ६ विजवे कार्य प्रा. लि., ग्रीन केयर एग्रीटेक प्रा. लि., वास्तुम इण्डिया लि., लखनऊ इन्फ्रासिटी प्रा. लि., टेक्नों नोटिस प्रा. लि., ग्रीन अर्थ इण्डिया लिमिटेड समेत कई अन्य नामों से कम्पनी बनाकर रकम निवेश करा ठगी करते हैं।श्रीपति लाल ने विशुन पाल सिंह निवासी सैनिक हाऊसिंग सोसाइटी, थाना सरोजनी नगर, लखनऊ के साथ मिलकर रकम हड़प ली है। 30 अप्रैल 22 को उसने मध्यस्थों पर दबाव बनाया तो उसे रकम भूल जाने और जान से मार डालने की धमकी दी गई। दोनों मध्यस्थों समेत वास्तुम इन्फ्रालैण्ड प्रा. लि. के प्रबंध निदेशकों मुकेश सिंह निवासी सैनिक हाउसिंग सोसाइटी सरोजनी नगर, थाना सरोजनी नगर, लखनऊ, राना अजय सिंह निवासी मानस जागृति नगर बादलीखेड़ा, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ व सुमित चौहान निवासी सत्यलोक कॉलोनी जागृति नगर, बादली खेड़ा, मानसनगर, थाना सरोजनी नगर, लखनऊ और मुकेश सिंह के पिता विशुन पाल सिंह के खिलाफ पुलिस और एसएसपी को शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जूडि) प्रथम सोनल उपाध्याय की अदालत ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।इस मामले मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडेय का कहना है कि पोंजी कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी के मामले में अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराई जा रही है।

लखनऊ में 23 नवंबर को होगी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (लखनऊ मंडल) की समन्वय बैठक

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (लखनऊ मंडल) की समन्वय बैठक आगामी 23 नवंबर को लखनऊ में आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता संगठन को मजबूत बनाने के लिए परस्पर समन्वय स्थापित करने हेतु प्रेरित करेंगे व एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी विस्तारीकरण पर चर्चा करेंगे। बैठक में विशिष्ट अतिथि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) के प्रांतीय महासचिव डॉ. कृष्ण गोपाल गुप्ता लखनऊ मंडल के सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई तथा लखीमपुर जनपदों की जिला इकाइयों की समीक्षा करेंगे। बैठक का संचालन, लखनऊ मंडल के अध्यक्ष व एसोसिएशन के कर्नाटक प्रभारी, अतुल कपूर करेंगे। लखनऊ मंडल के प्रवक्ता अम्बरीष कुमार सक्सेना पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं व जिला पत्रकार स्थाई समितियों के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। यह जानकारी देते हुए समन्वय बैठक के आयोजक व लखनऊ जनपद के महामंत्री आर. एल. पाण्डेय ने बताया कि उक्त बैठक आगामी 23 नवंबर को श्री शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सभागार में शनिवार को 11:00 बजे से प्रारंभ होगी। प्रोफेसर विवेक मिश्रा मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ मंडल के सभी जिलों में एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए परस्पर समन्वय स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन करेंगे। बैठक में हरदोई के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह, सीतापुर के जिला अध्यक्ष सुदीप मिश्रा, लखीमपुर के जिला अध्यक्ष नितेश अग्रवाल, रायबरेली के जिला अध्यक्ष चंद्रेश त्रिवेदी, लखनऊ के जिला अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव व उन्नाव के जिला अध्यक्ष सुयश बाजपेई सहभागिता करेंगे।

परिवहन विभाग में एक मुश्त समाधान योजना-2024 के तहत उठायें छूट - ऋतु सिंह

अयोध्या। आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह ने बताया गया कि परिवहन विभाग में एक मुफ्त समाधान योजना 2024 के तहत वाहन सावधानी लाभ उठाये।यह लाभ तीन माह की अवधि के लिए वाहन स्वामियो के लागू होगी। उन्होंने बताया कि न्यायलय मे लंबित मामले सहित कई मामले का समाधान करे। वाहन स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) /कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटरयानों (7500 कि०ग्रा० सकल यान भार तक) के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 200/– रूपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में 500/–रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वाहन स्वामी अन्य योजनाओं का लाभ उठाये।

विद्युत मजदूर पंचायत अयोध्या संघ ने सौपा ज्ञापन

अयोध्या। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत अयोध्या के पदाधिकारियों ने जोनल अध्यक्ष के अध्यक्षता में गुरुवार को दोपहर 12:00 से शाम 5:00 बजे तक मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के जोनल अध्यक्ष के एन सिंह ने कहा

कि वार्ता द्वारा सुनवाई न होने पर संगठन लगातार आंदोलन करेगा। क्योंकि मुख्य अभियंता द्वारा बिजली कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है

जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।धरना का संचालन जिला कमेटी के अध्यक्ष देवनारायण शर्मा ने किया इस मौके पर राज बहादुर उपाध्याय,जय गोविंद, रघुवंश मिश्रा, सुशील मौर्य,सत्येंद्र पांडे,राम सिंह,राजेश यादव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

निर्माणाधीन मंदिर के प्रथम तल पर लगे कमजोर पत्थरों को निकाल कर लगाया जाएगा मकराना का पत्थर'

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।अयोध्या राम मंदिर के सामने महर्षि वाल्मीकि का मंदिर होगा, श्रद्धालुओ के प्रवेश करते ही दिखेंगे महर्षि वाल्मीकि, सप्त मंदिर के बीच सरोवर में बनाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा निर्माणाधीन प्रथम तल पर कुछ जगहों पर पत्थर में कमजोरी है, पत्थर की मोटाई वो मोटाई नहीं है जो मोटाई होनी चाहिए, वह कमजोर लग रहा है, कुछ जगहों पर पत्थर हटाकर मकराना के पत्थर लगाए जाएंगे। मंदिर परिसर में बनाए सप्त मंदिर बनाये जा रहे हैं, राम मंदिर के पहले होगा महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, प्रवेश करते ही श्रद्धालु दर्शन करेंगे महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि वाल्मीकि मंदिर के ठीक सामने सातवां मंदिर अगस्तय मुनि का होगा, सप्त मंदिर के बीच बनाया जाएगा एक छोटा सा सरोवर, सरोवर में आचमन कर श्रद्धालु सप्त मंदिर का दर्शन कर सकेंगे।

अयोध्या में महापर्व छठ पूजा पर उगते सूर्य को हजारों छठ वृद्धि महिलाओं ने दिया अर्घ्य'

अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गुप्तार घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। भोर होते ही महिलाएं अपने परिजनों के साथ गुप्तार घाट पर एकत्र हुईं और नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए भगवान भास्कर से अपने परिवार और समाज की सुख–समृद्धि और मंगल की कामना की। घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां छठी मैया के

भक्ति गीत और ढोल–नगाड़ों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने परंपरागत वेशभूषा में छठ पूजा की विधि का पालन करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। श्रद्धालुओं के बीच इस अवसर पर उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला, और लोग अपने परिजनों के साथ छठ पूजा के इस महापर्व में शामिल हुए।

सपा कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे... को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार पोस्टरवार जारी है। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में कहा गया है कि अगर बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा और एक रहेंगे तो 400 रुपये में मिलेगा। यह पोस्टर कांग्रेस नेता अजीत कुमार मौर्या की तरफ से लगाया गया है। बता दें कि सीएम योगी के बयान पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा था कि न बटेंगे न कटेंगे पीडीए संग रहेंगे। इस पोस्टर में भी पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के एक रहने की बात कही गई है। पोस्टर में दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ सभी धर्मों के लोगों को प्रदर्शित करते हुए एक तस्वीर भी लगाई गई है। पोस्टर में लिखा है.. न बटेंगे न कटेंगे एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा एक होंगे तो 400 रुपये में मिलेगा। इसी तरह, इसके पास एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें कहा गया है

कि पीडीए की होगी जीत–एकता की होगी जीत। गंगा–जमुना, तहजीब को न ही बंटने देंगे ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। यह पोस्टर सपा प्रवक्ता अभिषेक बाजपेई की तरफ से लगाया गया है। प्रदेश में नौ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। परिणाम की घोषणा 23 नवंबर को होगी। इस पोस्टरवार को उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की रोशनी में देखा जा रहा है।

यह नया भारत है, कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं - सीएम योगी

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था को जीवंत बनाए रखने का एक उदाहरण है। इस चराचर जगत की कोई भी वस्तु सूर्य देव की कृपा से ही आगे बढ़ती है। छठ जैसे कठिन व्रत के साथ व्रती और व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा ही संकल्प देश के प्रति भी होना चाहिए। राष्ट्रीय धर्म का पालन हर किसी को करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यही कर रहे हैं।

नया भारत है, कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं – योगी

5 अगस्त 2019 को मोदी की प्रेरणा से कश्मीर में 35 ए और धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद की तबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम किया गया था। यह नया भारत है। यह किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। यह एक भारत मजबूत भारत की दिशा में कदम है। योगी ने कहा कि जिस कश्मीर में लोग पत्थर मारते थे, आज वह कश्मीर भारत का स्वर्ग

बनने की ओर अग्रसर है।

कश्मीर में अब हिंदू सुरक्षित – योगी

आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में पर्यटक फिर से जाना प्रारंभ कर दिए हैं। जब धारा 370 के कारण जिस कश्मीर में व्यापक हिंसा होती थी, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था, जिस कश्मीर में वर्ष 1989 और 90 में लाखों कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 370 धारा को समाप्त करने का संकल्प लिया था। कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस की विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि आज वे धारा 370 को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ रहा है रू योगी

पूरा देश इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व को इससे खिलवाड़ करने की इजाजत देश कतई नहीं देता। जो धारा 370 खत्म हो चुकी है, उसे कभी लागू नहीं किया जा सकता। यह धारा आतंकवाद की जड़ है। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह लाखों निर्दोषों के खून से सनी हुई धारा है।

इस धारा ने कश्मीर के सामाजिक सद्भाव को तहस–नहस करने का काम किया था। कश्मीर में आतंकवाद का वेयरहाउस बन गया था। आज इस धारा को समाप्त कर जब कश्मीर मुख्य धारा से जुड़ रहा है, तब वहां की विधानसभा में इसे दोबारा लागू करने का प्रस्ताव निंदनीय है। देश इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना चाहते हैं। हर भारतवासी ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस को भी इस पर बोलना चाहिए, नहीं तो भारत में उसकी वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में 370 की हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भोजपुरी समाज को भोजपुरी बोली में पर्व की बधाई दी।

लखनऊ में शानदार कालोनी में होगा अपना घर, वृंदावन योजना के लिए पंजीकरण शुरू

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वृंदावन आवासीय योजना में भूखंडों की बिक्री प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप भी भूखंड खरीदने के इच्छुक हैं तो 30 नवंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं।

वृंदावन योजना में पीजीआइ के सामने से उतरेटिया रेलवे स्टेशन की ओर से जाने वाले मार्ग पर सेक्टर 20 में भूखंड का बड़ा हिस्सा खाली है, परिषद इसी को गेटेड कालोनी के रूप में संवारने जा रहा है, भूखंड आवंटन में एकमुश्त भुगतान करने वालों को वरीयता मिलेगी। परिषद ने योजना संख्या चार सेक्टर 20 में 284 भूखंड चिह्नित किया है, ये भूखंड 138, 148, 200 और 300 मीटर तक के हैं।

परिसर में क्या–क्या होगा?

परिसर में सड़क, सीवर सहित अन्य सुविधाएं मुहैया होंगी, हर भूखंड पार्क फेसिंग होगा, परिसर में ही बाजार आदि का भी प्रबंध हो रहा है। खास बात यह है

कि वृंदावन कालोनी में मूलभूत सुविधाएं पहले से हैं, भूखंड खरीदते ही उसे मन मुताबिक बनवाकर रह सकते हैं। इसी स्थल के पास ही डिफेंस एक्सपो मैदान भी है, जिस पर कंवेंशन सेंटर बनाने को आवास विकास परिषद का बोर्ड मंजूरी दे चुका है।

इस तरह करें आवेदन

आनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक को परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर आनलाइन रजिस्ट्रेशन फार प्लाट पर क्लिक करना होगा, आवेदन केवल आनलाइन ही स्वीकार होंगे। विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा, वेबसाइट पर आनलाइन नियम व शर्तें भी देख सकते हैं।

60 दिन में भुगतान पर पांच प्रतिशत की मिलेगी छूट

परिषद की ओर से लाटरी में नाम आने के बाद आवंटन पत्र जारी होगा। आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 60 दिन में भूखंड मूल्य का पूरा भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की विशेष छूट भी आवेदक को मिलेगी।

राहुल के बयान हास्यास्पद, कांग्रेस ने पिछड़ों के साथ अन्याय किया – मंत्री दिनेश प्रताप

लखनऊ, संवाददाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रायबरेली में अफसरों को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। इस पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान हास्यास्पद है। बैठक में राहुल गांधी ने किसी से परिचय नहीं लिया था बल्कि सभी अफसरों ने खुद अपना परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि न्यायपालिका में दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग नहीं हैं। इन जजों को मोदी सरकार ने नहीं कांग्रेस की सरकार में नियुक्त किया गया था। दलितों और पिछड़ों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। मोदी और योगी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। बता दें कि नेता विपक्ष व सांसद राहुल गांधी ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के अगले दिन नागपुर में आयोजित एक संविधान सम्मेलन में प्रशासनिक व्यवस्था में असमानता की बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं मंगलवार को रायबरेली में दिशा की बैठक में शामिल हुआ। गलती से मैंने कह दिया कि सभी अफसर अपना परिचय दें। परिचय शुरू हुआ तो उसमें मुझे एक भी दलित व ओबीसी नाम नहीं सुनाई दिया। राहुल गांधी का यह बयान पूरे दिन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली में 80 प्रतिशत अधिकारी दो विशेष जातियों से हैं।

देश में अशांति फैलाने के लिए दिया गया बयान

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में अशांति फैलाने के लिए ये बयान दिया है। 1951 से कांग्रेस ने दलितों–पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। 1951 से आज तक रायबरेली में किसी दलित–पिछड़े को टिकट नहीं दिया गया है। वायनाड से किसी दलित को टिकट क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। राहुल गांधी का बयान देश में सद्भावना को खत्म करने वाला है। वो देश को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं।

10वीं मंजिल से गिरकर रिटायर्ड जज की बेटी की मौत, पति पर हत्या का आरोप

लखनऊ, संवाददाता। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन कालोनी के आरावली एन्क्लेव में बुधवार रात 42 वर्षीय प्रीति की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मामले में उनके पिता सेवानिवृत्त जज एसपी तिवारी ने आरोप लगाया है कि दामाद रवींद्र कुमार द्विवेदी ने पहले बेटी को बेरहमी से पीटा। अधमरा होने पर 10वीं मंजिल की बालकनी से फेंककर प्रीति की हत्या कर दी। उन्होंने पीजीआइ थाने में तहरीर दी है। इस मामले में डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही है। पीड़ित एसपी तिवारी ने बताया कि बेटी प्रीति का विवाह 29 नवंबर 2012 को बैंक कर्मचारी रवींद्र कुमार द्विवेदी से किया था। शादी के बाद से ही आए दिन रुपयों की मांग को लेकर दामाद, बेटी को प्रताड़ित करता था। ऐसे में वह हर माह पहली तारीख को 10 हजार रुपये उसके बैंक खाते में भेज देते थे। कुछ समय पहले रुपये भेजने में देरी हो गई तो उनके साथ फोन पर गाली–गलौज की। इसके बाद रुपये भेजना बंद कर दिया। आए दिन विवाद होता तो बेटी को किसी तरह समझाकर

शांत करवा देते।

वहीं, मंगलवार को बेटी का फोन आया कि रवींद्र ने बहुत पीटा है। उनका कहना है कि फ्लैट का 80 लाख रुपये लोन है। गोमतीनगर विस्तार वाला प्लाट बेंच कर लोन को खत्म करवा दीजिए। इसके बाद फोन काट दिया। वह कुछ कर पाते कि बुधवार शाम को उनको सूचना मिली कि प्रीति की बालकनी से गिरने से मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। परिवार में दो बेटे विश्वम और आंजनेय हैं।

पीटकर गेट से भगा दिया

पीड़ित पिता के मुताबिक बेटी ने उन्हें जब मारपीट करने की सूचना दी तो वह वह तत्काल पत्नी इंद्रा तिवारी के साथ पहुंचे और गेट खटखटाया। इसपर रवींद्र ने गेट खोलकर उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। यही नहीं, उनको पीटते हुए भगा दिया।

वर्ष 2022 से इस फ्लैट में रह रहे थे

वर्ष 2022 में रवींद्र पत्नी प्रीति और बच्चों के साथ शिफ्ट हुआ था। बी–12 टावर में सिर्फ यही परिवार रहता था। ऐसे में घटना कैसे हुई और उस वक्त क्या हुआ कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस अन्य माध्यमों से जांच कर रही है।

घटना के बाद से पति फरार

घटना होने के बाद से रवींद्र बच्चों को लेकर फरार हो गया है। अन्य लोगों से पूछताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चल सका है। घटना के समय क्या हुआ इसकी जानकारी बच्चों के जरिए हो सकती है।

एनसीईआरटी के पाठ्य क्रम में होने वाला है बदलाव

लखनऊ, संवाददाता। चार दिसंबर को होने वाले परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण–2024 में प्रदेश के 9,715 सरकारी व निजी स्कूलों के 2.90 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परख परीक्षा में कक्षा तीन, कक्षा छह व कक्षा नौ के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। भाषा, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषयों में उनकी समझ को आंका जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) इस सर्वे की मदद से आगे पाठ्यक्रम में जरूरी संशोधन व नई योजनाएं बनाएगी।

परख सर्वेक्षण की जिम्मेदारी

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को प्रदेश में परख सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डा. पवन कुमार ने बताया कि सर्वे का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य स्तर पर छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन, विश्लेषण और संवर्धन किया जाएगा।

10 हजार कक्ष निरीक्षक

सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य व जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं 10 हजार कक्ष निरीक्षक बनाए गए हैं। कक्ष निरीक्षकों में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रशिक्षुओं, बीएड व एमएड प्रशिक्षुओं, कालेज के छात्र व सेवानिवृत्त शिक्षक आदि शामिल हैं।

ओएमआर शीट पर परीक्षा देंगे विद्यार्थी

कक्षा तीन, कक्षा छह व कक्षा नौ के विद्यार्थी ओएमआर शीट पर परीक्षा देंगे।

कक्षा तीन के विद्यार्थियों को 90 मिनट में 45 सवालों का जवाब देना होगा। भाषा, हमारे आसपास की दुनिया व गणित विषय के 15–15 सवालों के जवाब देने होंगे। वहीं कक्षा छह के विद्यार्थियों को 51 सवालों का जवाब 90 मिनट में देना होगा।

संगठन चुनाव के लिए भाजपा ने की चुनाव अधिकारियों की घोषणा

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन के चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा ने चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश के संगठन चुनाव अधिकारी डा. महेन्द्र नाथ पांडेय ने बुधवार को चुनावों के लिए नियुक्त किए गए जिला चुनाव अधिकारियों के नामों की घोषणा की। पांडेय ने बताया कि संगठन चुनाव के लिए नौ नवंबर को जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। बूथ समिति के चुनाव 15 नवंबर से प्रारंभ होकर 30 नवंबर के मध्य संपन्न होंगे। बूथ समिति चुनाव के बाद मंडल और जिला संगठन के चुनाव होंगे। पांडेय ने बताया कि सहायक चुनाव अधिकारी मुकुट बिहारी वर्मा (कानपुर क्षेत्र), रंजना उपाध्याय (अवध क्षेत्र), राजेंद्र तिवारी (काशी क्षेत्र), अनिल चौधरी (पश्चिम क्षेत्र), कमलेश कुमार (गोरखपुर क्षेत्र) और हरीश कुमार सिंह (ब्रज क्षेत्र) संगठन चुनाव का कार्य देखेगें। वहीं, प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह और अरुणकांत त्रिपाठी प्रदेश चुनाव अधिकारी के साथ समन्वय का कार्य करेंगे। पार्टी ने संगठन चुनाव के लिए नियुक्त 98 जिला चुनाव अधिकारी की सूची भी जारी कर दी है।

उप चुनाव के कारण निपुण मूल्यांकन टेस्ट अब 25 से

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों का निपुण मूल्यांकन टेस्ट अब 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक होगा। पहले यह टेस्ट 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आयोजित किया जाना था। विधानसभा उप चुनावों की तारीख में परिवर्तन होने के कारण अब तिथियों में बदलाव कर दिया गया है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से परीक्षा की नई समय–सारिणी जारी कर दी गई है। परीक्षा की नई समय–सारिणी के अनुसार लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर व बरेली मंडलों में 25 नवंबर को कक्षा एक से कक्षा तीन तक के छात्रों की और 26 नवंबर को कक्षा चार से कक्षा आठ तक के छात्रों का टेस्ट होगा। गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़ व झांसी मंडलों में 27 नवंबर को कक्षा एक से कक्षा तीन तक और 28 नवंबर को कक्षा चार से कक्षा आठ तक के छात्रों की परीक्षाएं होंगी।

यूपी में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, कंपनियों को नोटिस जारी

लखनऊ, संवाददाता। प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीकी जांच में फेल साबित हुए हैं। यूपी पावर कारपोरेशन की उच्च स्तरीय टीम ने स्मार्ट मीटर में गंभीर तकनीकी खामियां पकड़ी हैं और संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर को लेकर पूर्व में ही पावर कारपोरेशन को आगाह किया था। पावर कारपोरेशन के निदेशक कामर्शियल निधि कुमार नारंग ने तकनीकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता कंपनी पोलरिस, इन टैलीस्मार्ट व जीएमआर के सीईओ को नोटिस भेजा है और तत्काल कमियों में सुधार करने का निर्देश दिया है।

यूपी में अब तक लगे लगभग 2.75 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर

प्रदेश में अब तक लगभग 2.75 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनमें 90 प्रतिशत इन्हीं कंपनियों के हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर

कारपोरेशन की उच्च स्तरीय आइटी जांच में जो कमियां सामने आईं हैं, उनमें पता चला है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर गलत पावर फैक्टर रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी आरटीसी दो घंटे में ट्रिप कर रही है, साथ ही पीटी रिसिवो गलत मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता रहा है। यह तकनीकी मानक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुख्य आधार होता है।

कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की मांग

उन्होंने कहा कि जो कमियां सामने आईं हैं, उससे साफ पता चल रहा है।

संक्षिप्त खबरें

टावर पर चढ़ा रोडवेज बस का संविदा चालक

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली में बृहस्पतिवार दोपहर सपा कार्यालय के पास एक टावर पर अलीगढ़ निवासी रोडवेज संविदा चालक राजू सैनी चढ़ गया। इससे वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और दमकल को दी। पुलिसकर्मी राजू को समझा बुझा कर नीचे उतराने की प्रयास करने लगे। मगर वह नहीं माने। उनकी पत्नी भावना ने अधिकारियों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि नौकरी को लेकर पति की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए वह टावर पर चढ़े हैं। वहीं, दमकलकर्मी ने थोड़ी देर में राजू को सकुशल नीचे उतार लिया।

मोबाइल पर बात कर युवक ने लगा लिया फंदा

लखनऊ, संवाददाता। कैंट के अर्जुनगंज में श्याम मिष्ठान भंडार के कर्मचारी हरदोई के अतरौली स्थित श्यामदासपुर निवासी विशाल सिंह (20) ने कमरे में फंदा लगा लिया। परिजनों का दावा है कि आत्महत्या से पहले वह किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने जांच की मांग की है। विशाल तीन साल से नमकीन बनाने का काम करते थे। दुकान के बगल में बने मकान की तीसरी मंजिल पर साथी कारीगरों संग रहते थे। उनके फुफेरे भाई शिवा सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह विशाल की मां शीला ने बात करने के लिए कॉल लगाई, पर फोन रिसीव नहीं हुआ। जानकारी पर साथी जब कमरे पर पहुंचा तो विशाल का शव पंखे में गमछे के सहारे लटका मिला। परिवार में पिता सुनील सिंह मां शीला, भाई शिवम,रिंकू,बहन शिवानी है।

किराये के मकान में बना रहे थे फर्जी अंकपत्र

लखनऊ, संवाददाता। पेपरमिल कॉलोनी में किराये का कमरा लेकर फर्जी अंकपत्र व प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का राजफाश कर महानगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि, सरगना पकड़ से दूर है। आरोपी विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों के जाली अंकपत्र बनाकर बेचते थे। पकड़े गए आरोपी के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, पेपर कटिंग मशीन और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी बिहार के हसनपुरा सिवाह निवासी राम प्रकाश वर्मा है। मुख्य आरोपी व सरगना मथुरा निवासी मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगे राम भाग निकला। सरगना अनैतिक देह व्यापार में भी संलिप्त रहा है। आरोपी पर कई थानों में केस दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मनीष राम प्रकाश से कंप्यूटर ऑपेरटर का काम करवाता था। राम प्रकाश वर्तमान में इंदिरा नगर में रह रहा था। इंस्पेक्टर के अनुसार मनीष की तलाश में टीमें गठित की गई हैं।

छूटने के बाद फिर से शुरू कर दिया फर्जीवाड़ा

इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरोह का सरगना पूर्व में जाली अंकपत्र बनाने के आरोप में जेल भेजा गया था। हालांकि, छूटने के बाद फिर से फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। आरोपी ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है।

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म

लखनऊ, संवाददाता। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और देह व्यापार के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए युवती ने मड़ियांव थाने में केस दर्ज कराया है। युवती के अनुसार, दो साल पहले रोहित गुप्ता नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। उसने पहले उन्हें प्यार के जाल में फंसाया और फिर दुष्कर्म किया। शादी की बात कही तो आरोपी ने मारपीट की। इस बीच पीड़िता को पता चला कि आरोपी रोहित के संबंध उनकी भाभी से भी हैं।

पड़ोसियों की पिटाई से आहत किसान ने कर ली खुदकुशी

लखनऊ, संवाददाता। रहीमाबाद के मुड़ियारा गांव में किसान रामजीवन (40) ने पड़ोसियों की पिटाई से आहत होकर बुधवार रात फंदा लगा लिया। मृतक की पत्नी श्रीमती ने खुशीराम, श्रीराम और उनकी मां के खिलाफ पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कराया है। किसान के बड़े भाई रामबिलास ने बताया कि रामजीवन बुधवार देर रात खाना खाकर लेट गया था। बृहस्पतिवार सुबह जब परिजन उठे तो रामजीवन नहीं थे। सुबह सात बजे ग्रामीणों से पता चला कि रामजीवन का शव शंकर के बाग में पेड़ में रस्सी के सहारे लटक रहा है। पुलिस ने छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामजीवन की पत्नी श्रीमती के मुताबिक पांच नवंबर को नाली के विवाद के चलते पड़ोसी खुशी राम, श्रीराम व श्रीराम की माता ने देवर मनोज को पीटा था। विरोध पर छह नवंबर को आरोपियों ने घर में घुसकर श्रीमती और रामजीवन के साथ मारपीट की थी औ बदनाम करने की धमकी दी थी। इससे आहत होकर पति ने आत्महत्या कर ली। परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चे साक्षी, साहिल व आठ माह का कार्तिक है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।